GOVT PROMISES VARIOUS CONCESSIONS TO FIRMS

Cab nod for 30% land subsidy for multi-modal logistics parks

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The state cabinet on Tuesday approved the Multi-Modal Logistics Park Policy-2024 that will allow companies investing in this sector to receive upfront land subsidies and various other concessions from the govt.

Officials said a company establishing a multi-modal logistics park will be given a 30% upfront land subsidy on plots leased by industrial development authorities or any state govt agency.

They said if an investor does not commence operations within the eligible investment period, the govt agency will recover the subsidy with 12% interest.

Such applicants will be exempted from all internal development charges.

IANS

CM Yogi Adityanath chairs a cabinet meeting at his official residence in Lucknow on Tuesday

They added that such companies will also receive a 100% exemption on stamp duty. Projects benefiting from this policy will not receive incentives under any other state govt policy or scheme.

However, before granting exemptions under the policy, opinions must be sought from the finance, law, institutional finance, housing and urban planning, revenue, stamp and registration, state tax, planning, energy and home departments.

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** कैबिनेट ने मंगलवार को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को मंजूरी दे दी है। इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी के साथ-साथ कई और रियायतें भी देगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाली कंपनी को 30 प्रतिशत की अप फ्रंट लैंड सब्सिडी दी जाएगी।

जल जीवन मिशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी : जल जीवन मिशन परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वनने वाली विभिन्न संरचनाएं जैसे ट्यववेल वनाने, पाइपलाइन विछाने पर खर्च होने वाली धनराशि का पूरा वोझ सरकार उठाएगी। सरकार पर करीव ₹5,100 करोड़ का अतिरिक्त वोझ आएगा।

3,000 बसें खरीदी जाएंगी : यूपी रोडवेज के वेड़े को मजवूत करने के लिए 3,000 डीजल वसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए पिछले अनुपूरक वजट में ₹1,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था। कैविनेट ने इसके खर्च को अनुमोदित कर दिया है।

जल भराव खत्म करने को ₹1,000 करोड़ : वारिश या अन्य मौके पर शहरों में होने वाल जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए अर्वन फ्लड एवं स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना शुरू होगी। इस पर पहले चरण में ₹1,000 करोड़ खर्च होंगे। कैविनेट ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।

Nod to multi-modal logistics parks policy

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

LUCKNOW: In an obvious bid to attract investment in the logistics sector, the state cabinet on Tuesday approved multi-modal logistics parks (MMLP) policy 2024 providing for special incentives to set up multi-modal logistics parks in Uttar Pradesh.

Chief minister Yogi Adityanath presided over the meeting of the state cabinet that approved the policy providing for incentives for setting up logistics parks.

Under the provisions of the policy, projects with a minimum investment of Rs 1,000 crore would be eligible for investment.

Those applying to set up a project under the policy should be registered as a Fortune Global 500, a Fortune India 500 company on the date of application or willing to make foreign direct investment of Rs 100 crore in Uttar Pradesh.

The policy provides for 30 percent upfront land subsidy for the projects. The land subsidy would be given only on the land allocated by the state's industrial development authority or any other government institution.

UNDER THE PROVISIONS OF THE POLICY, PROJECTS WITH A MINIMUM INVESTMENT OF RS 1,000 CRORE WOULD BE ELIGIBLE FOR INVESTMENT

The applicant would also be exempted from all the development fees that would be borne by the respective development authorities.

There would be 100% exemption in the stamp duty on the land to be given on lease to the applicant. Various other facilities would also be given.

The logistics, which was 215 billion USD industry in 2020 in India, is likely to grow to $360 billion by 2032.

उप्र में बनेंगे मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क

लाजिस्टिक पार्कों में हो सकेगा 100 करोड़ तक का विदेशी निवेश

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) का भी निर्माण किया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एमएमएलपी में 1,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपये तक का विदेशी निवेश भी किया जा सकेगा। सरकार भूमि खरीद पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान करेगी। निवेश के लिए फार्च्यून ग्लोबल 500 अथवा फार्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध कंपनियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क नीति के तहत आवेदन करने वाली इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की वर्तमान दर में अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत कम करके भूमि आवंटित करेंगे। नीति में स्पष्ट किया गया है कि पात्र निवेश की अवधि तक भूमि संबंधित प्राधिकरण के पास बंधक रहेगी। अनुमन्य समय में परियोजना के पूरा होने के बाद भूमि बंधन मुक्त कर दी जाएगी। अगर आवेदक निवेश अवधि के भीतर संचालन करने में विफल रहते हैं तो भूमि पर दी गई छूट को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूला जाएगा।

अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस, ब्राजील व यूनाइटेड अरब अमीरात की नीति का अध्ययन करके बनाई गई उत्तर प्रदेश की नीति के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल संस्था बनाया गया है। एमएमएलपी एक्सप्रेसवे व हाईवे से जुड़े बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की किसी संस्था से पट्टे पर ली गई भूमि पर 100 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट राज्य सरकार की संबंधित संस्था के प्रमुख के पक्ष में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। लाजिस्टिक पार्कों के लिए 17,000 एकड़ की भूमि विभिन्न हिस्सों में चिह्नित की जा चुकी है।

कैबिनेट के फैसले

- इन्वेस्ट यूपी होगी नोडल संस्था
- 1,000 करोड़ का न्यूनतम निवेश
- निवेशकों को भूमि खरीद पर सरकार देगी 30% तक की छूट

ये सुविधाएं होंगी उपलब्ध

एमएमएलपी में फ्रेट एग्रीगेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी माडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, भंडारण एवं वेयर हाउसिंग, वस्तुओं की छंटनी, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, रिपैकेजिंग, टैगिंग, लेबलिंग, वितरण, उपभोक्ताओं को वितरण, कार्गो व कंटेनरों का स्थानांतरण, खुला व बंद भंडारण, नियंत्रित तापमान में भंडारण, कस्टम बांडेड वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर टर्मिनल, पार्क के अंदर वस्तुओं को लाने व रखने के लिए सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सड़कें, आंतरिक सार्वजनिक परिवहन, बिजली, ग्रीन बेल्ट, जल वितरण, सीवेज तथा जल निकासी, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व अग्निशमन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं एमएमएलपी में अतिथि गृह, कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैंक व प्रशासनिक कार्यालय की भी सुविधा रहेगी।

सरोजनी नगर में बनेगा अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय का परिसर

अंग्रेजी व विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र के चिकौली गांव में बनाया जाएगा। यहां 2.32 हेक्टेयर जमीन देने को मंगलवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। राज्य सरकार यह जमीन निशुल्क देगी। यह जमीन सर्किल रेट के आधार पर करीब 9.29 करोड़ रुपये कीमत की है। विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का यह क्षेत्रीय परिसर वर्ष 1979 से मोती लाल नेहरू मेमोरियल सोसाइटी के मोती महल परिसर में किराए के भवन में चलाया जा रहा था। डेढ़ साल पहले कानपुर रोड़ स्थित बीएसएनएल के आरटीटीसी कांप्लेक्स में स्थानांतरित कर दिया गया और अभी यह वहीं चलाया जा रहा है। फिलहाल प्रति वर्ष दो हजार से लेकर ढाई हजार तक छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। छात्रों को अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं में दक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश में ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी।

आयुष्मान योजना में श्रमिकों को पंजीकरण शुल्क में छूट

कैबिनेट की बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

Rs 5 crore for four tourist sites in Lko

HT Correspondent

letters@htlive.com

LUCKNOW: The Uttar Pradesh Department of Tourism has allocated ₹5 crore to enhance tourism sites in Lucknow, aiming to boost the city's cultural and historical appeal. The Sai Riverbank in Sarojininagar will see significant development, including the construction of a ghat with stairways, solar lighting, benches, and pathways, providing a tranquil environment for visitors. A budget of ₹2 crore has been sanctioned for the project.

The historic Bada Shivala Shri Siddhnath temple in Sadar Tehsil will undergo beautification with a budget of ₹1.02 crore, of which ₹60 lakh has already been released.

The development will include rest houses, benches, signage, and toilets to improve visitor convenience.

Nanak Sahi Math, an important religious site, will be developed with an allocation of ₹1 crore, featuring solar lighting, benches, gazebos, and horticulture. ₹60 lakh has already been disbursed for this project.

SHAHEED RAJA DIGVIJAY SINGH MEMORIAL IN UMARIA VILLAGE WILL UNDERGO DEVELOPMENT WITH ₹1 CRORE

Additionally, the Shaheed Raja Digvijay Singh Memorial in Umaria Village will undergo development with ₹1 crore, which will include access roads, lighting, benches, a children's park, and a ghat on the Gomti River.

Tourism Minister Jaiveer Singh highlighted that these projects will enhance facilities for tourists and devotees, preserving Lucknow's heritage while boosting tourism and the local economy.